Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN: 3048-6513 (Online)
Volume: 2 Issue: 5 || October 2025 || DOI: 10.5281/zenodo.17466271

भारत अमेरिका के सम्बन्ध के विविध आयाम

डॉ0 हिमांशु यादव[1]

संक्षेपिका

स्वतंत्रता के तुरंत उपरांत भारत और अमेरिका सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में तनाव और अधिक बढ़ गए थे। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के समय दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध और कटुतापूर्ण हो गए थे। निःसन्देह भारत-अमेरिका सम्बन्धों में प्रगति धीमी थी। हालाँकि, 1990 के दशक में भारत की आर्थिक नीतियों में बदलाव और पिछले दशक में हुई अभूतपूर्व प्रगति ने दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध को रणनीतिक और बहुआयामी बना दिया है। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार एवं 'वैश्वीकरण-निजीकरण-उदारीकरण' का प्रयोग, भारत द्वारा सन् 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण के साथ-साथ अमरीका को चीन एवं इस्लामिक कट्टरवाद से मिल रही चुनौतियाँ आदि ने इक्कीसवीं सदी में दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों की पृष्ठभूमि निर्मित की है। भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी के लिए यू.एस.-इंडिया कॉम्पैक्ट शुरू किया है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। व्यापार क्षेत्र की बात करें तो दोनों देशों ने सन् 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों देशों के मध्य आतंकवाद रोधी सहयोग में सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग और आतंकवाद रोधी भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से नियमित संवाद शामिल है। वर्ष 2017 में दोनों पक्षों ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नामित आतंकवादी सूची प्रस्तावों पर एक संवाद शुरू किया है।

वर्तमान में दोनों देश क्वाड के सदस्य है, जिसे चीन को लक्षित कर संगठित किया था। विगत कुछ वर्षो में, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है जो दोनों देशो की मधुर होते सम्बन्ध को दर्शाता है मगर अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाये जाने के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इतना ही नहीं शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सक्रिय सहभागिता और भारत-चीन-रूस के मध्य बढ़ती निकटता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ क्वाड प्रसंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है।

मुख्य शब्दः*-रक्षा सम्बन्ध, सहभागिता, परमाणु ऊर्जा, महाशक्ति, शक्ति सन्तुलन,पूंजीवादी लोकतान्त्रिक,शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स आदि।*

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी ने भारत-अमरीका सम्बन्धों को एक विस्तृत आयाम दिया है। सन् 2005 में 'भारत-अमरीका रक्षा सम्बन्धों के नये ढाँचे, आयुध निर्माण में निरन्तर बढ़ती सहभागिता, सन् 2007 में 'शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग' पर बनी सहमति, अमरीका द्वारा 'परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह' एवं 'मिसाइल टेक्नॉलॉजी कण्ट्रोल एण्ड रिजीम' में सदस्यता के लिए अमरीका द्वारा भारत का समर्थन किया जाना, दक्षिण एशिया एवं हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को अमरीका द्वारा अनदेखा न करना आदि सभी तथ्यों ने भारत एवं अमरीका को एक दूसरे के अधिक निकट खड़ा किया है। दोनों देशों के मध्य हो रहे सैन्य अभ्यास एवं दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एक-दूसरे देश

[1] राजनीति विज्ञान विभाग, एस0पी0एम0 डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

की पास्परिक यात्रा में 'निरन्तरता' एवं 'सघनता' ने दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध को अधिक मधुरता प्रदान की है। गणतंत्र दिवस 2015 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमरीकी राश्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की भागीदारी तथा लगातार तीन भारतीय प्रधानमन्त्रियों - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ0 मनमोहन सिंह एवं श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमरीकी संसद 'कांग्रेस' को सम्बोधित किया जाना दोनों देशों के रिश्तों की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करता है। एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिए अमरीका से ये नजदीकियाँ मील का पत्थर सिद्ध हो सकती हैं। भारत अमरीका सम्बन्धों की जटिलता एवं वर्तमान परिस्थितियों को समझने हेतु हमें दोंनों देशों के सम्बन्धों के सन्दर्भ में द्वितीय विश्वयुद्ध की प्राचीनता तक जाना होगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उस समय समूचा विश्व दो परस्पर विरोधी खेमों में विभक्त था, जिसमें प्रथम खेमें का नेतृत्व 'पूंजीवादी लोकतान्त्रिक' देश संयुक्त राज अमरीका के हाथों में था जबकि दूसरे खेमें का नेतृत्व 'साम्यवादी' देश सोवियत संघ (यू0एस0एस0आर0) के हाथों में था। नव स्वतंत्र भारत को किसी भी खेमें में शामिल होना न तो स्वीकार्य था और न ही भारत के राश्ट्रीय हितों की दृश्टि से तार्किक। ऐसी स्थिति में भारत 'गुट निरपेक्षता' की नीति का अवलम्बन करना तार्किक एवं श्रेश्ठतम् समझा। अमरीका द्वारा भारत की इस नीति को अमरीका विरोधी बताया गया जैसा कि उसका यह मानना था कि जो अमरीका के साथ नहीं वह अमरीका विरोधी है। ऐसी स्थिति में अमरीका अपनी तात्कालिक विदेश नीति के मूल उद्देश्य (सोवियत संघ एवं साम्यवादी चीन जैसी शक्तियों को बढ़ने से रोकना) की प्राप्ति हेतु पाकिस्तान को एशिया में शक्ति सन्तुलन स्थापित करने हेतु उपयोग करना प्रारम्भ किया। इसी पृश्ठभूमि में भारत-अमरीका सम्बन्ध का विकास हुआ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त, जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उस समय लगभग समूचा विश्व दो वर्गों में विभक्त था। ऐसी स्थिति में नवस्वतन्त्र भारत के लिए किसी भी वर्ग में सम्मिलित होना न तो स्वीकार्य था और न ही औचित्यपूर्ण। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति के लिए 'गुट निरपेक्षता की नीति' को प्रमुख निर्धारक तत्व चुना। अमरीका ने भारत द्वारा उठाये गये इस कदम को अमरीका विरोधी माना तथा दक्षिण एशिया में शक्ति सन्तुलन की स्थापना हेतु पाकिस्तान को चुना। गौरतलब है कि प्रारम्भ से ही पाकिस्तान के साथ भारत का सम्बन्ध न केवल अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरा रहा है बल्कि भारत में हुये अधिकांश आतंकवादी घटनाओं का सम्बन्ध भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहा है। ऐसी स्थिति में बीसवीं सदी के अन्तिम दशक तक भारत अमरीका सम्बन्ध व्यापक उतार-चढ़ाव के साथ-साथ बीमारू अवस्था में था। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार एवं 'वैश्वीकरण-निजीकरण-उदारीकरण' का प्रयोग, भारत द्वारा सन् 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण के साथ-साथ अमरीका को चीन एवं इस्लामिक कट्टरवाद से मिल रही चुनौतियाँ आदि ने इक्कीसवीं सदी में दानों देशों के मध्य सम्बन्धों की पृश्ठभूमि निर्मित की। इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही अमरीका के न्यूयार्क शहर स्थित 'विश्व व्यापार केन्द्र' पर हुये आतंकवादी हमले ने भारत-अमरीका सम्बन्ध के समूचे परिदृश्य को ही परिवर्तित कर दिया। इस घटना के उपरान्त दोनों देशों द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी। यही वह परिस्थिति है जो भारत-अमरीका के मध्य सम्बन्धों के प्रारम्भिक बिन्दु का निर्धारण करती है।

यद्यपि कि इस पृश्ठभूमि में दोनों देशों की आवश्यकताएँ पृथक-पृथक थीं तथापि ये आवश्यकताएँ दोनों देशों के राश्ट्रीय हित के सन्दर्भ में समरूप होने के कारण एक दूसरे की सहगामी सिद्ध हुयीं एवं दोनों देशों को अधिक नजदीक ले आयीं। उपरोक्त वर्णित पृश्ठभूमि में विकसित भारत-अमरीका सम्बन्धों को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है :-

आतंकवाद विरोधी सहयोग :

भारत एवं अमरीका के मध्य विकसित होते सम्बन्धों में आतंकवाद विरोधी भावना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ध्यातव्य है कि दोनां ही देश प्रजातान्त्रिक देश हैं तथा दोनों ही के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सन् 2001 में जहाँ अमरीका में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर राश्ट्रपति बने वहीं यह वर्श अमरीका के न्यूयार्क स्थित 'विश्व व्यापार केन्द्र' ;ॅवतसक ज्तंकम ब्मदजतमद्धपर हुये

आतंकी हमले का साक्षी भी रहा। 11 ''सितम्बर को हुये इस हमले के बाद दोनों ही देश आतंकी गतिविधियों के विरूद्ध मिलकर कार्य करने हेतु प्रेरित हुये, जिसके सन्दर्भ में भारत द्वारा अमरीका को आतंकवाद के विरूद्ध शर्तरहित समर्थन देने की घोशणा की गयी। इस बीच 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर एक नाकाम आतंकी हमला किया गया जिस पर अमरीका द्वारा भारत के पक्ष में प्रतिक्रिया दी गयी। इसके उपरान्त भारत एवं अमरीका के मध्य न केवल सैन्य सहयोग पर सहमति बनी बल्कि दोनों देशों के मध्य 'द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास' का आरम्भ भी हुआ।

26 नवम्बर, 2008 के मुम्बई हमले की घटना ने एक बार फिर दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध हेतु 'आतंकवाद विरोधी नीति' को महत्वपूर्ण बना दिया। इस घटना के उपरान्त सन् 2010 में अमरीकी राश्ट्रपति बराक ओबामा भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान 26/11 की घटना के लिए स्पश्ट शब्दों में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया तथा ऐसी घटना दुबारा न होने की चेतावनी भी दी। आगे चलकर अमरीका द्वारा मुम्बई हमले के मास्टरमाइण्ड हाफिज सईद को न केवल वांछित आतंकी घोशित करते हुये उसके ऊपर एक करोड़ इनाम राशि की घोशणा की गयी बल्कि लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन भी घोशित किया गया। अमरीकी राश्ट्रपति के 2010 की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 'भारत-अमरीका आतंकवाद विरोधी सहयोग' प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के साथ-साथ ओबामा द्वारा 'भारत-अमरीका गृह सुरक्षा वार्ता' आरम्भ करने की घोशणा की गयी तथा सन् 2011 में दोनों देशों के मध्य प्रथम गृह सुरक्षा वार्ता सम्पन्न हुयी। सन् 2013 में प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा दिये गये संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद विरोधी सहयोग की वचनबद्धता को दुहराया गया। सन् 2014 में आई0एस0आई0एस0 ;प्ैप्द्धकी स्थापना से न केवल वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत खतरा उजागर हुआ है बल्कि दोनों देशों के मध्य आतंकवाद विरोधी सहयोग की वचनबद्धता का महत्व भी बढ़ गया है। इसी बीच सितम्बर सन् 2014 में भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अमरीका यात्रा पर गयें इस यात्रा के दौरान आतंकवाद के विरूद्ध सतत वैश्विक प्रयास पर बल दिया गया तथा भारत द्वारा मुम्बई घटना के लिए दोशियों को कटघरे में खड़े करने की अपनी मांग को दुहराया भी गया।

जनवरी 2018 में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोक दिया जाना भारतीय दृश्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अमरीका के इस फैसले के उपरान्त अन्तर्राश्ट्रीय दबाव में ही सही किन्तु पाकिस्तान द्वारा वांछित आतंकी हाफिज सईद के संगठन को चन्दा देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ध्यातव्य है कि भारत में सर्वाधिक आतंकी हमले लश्कर-ए-तैयबा एवं जैस-ए-मोहम्मद द्वारा किये गये हैं। गौरतलब है कि हाफिज सईद न केवल लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है बल्कि 26 नवम्बर 2008 को हुये मुम्बई आतंकी हमले का मास्टर-माइण्ड भी है। अमरीका द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय कूटनीतिक दृश्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है किन्तु यह संदेहास्पद है कि अमरीका अपने इस कदम पर कब तक अडिग रहता है क्योंकि अमरीकी आर्थिक हित (अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहयोग राशि का प्रयोग प्रायः अमरीका से ही हथियार खरीदनें में प्रयुक्त होता रहा है) एवं अफगानिस्तान में अमरीकी सामरिक हित की दृश्टि से पाकिस्तान की भूमिका को अमरीका द्वारा नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता। फिर भी अमरीका द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध उठाया गया यह कदम सराहनीय है।आतंकवाद रोधी सहयोग में सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग और आतंकवाद रोधी भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से नियमित संवाद शामिल है। वर्ष 2017 में दोनों पक्षों ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नामित आतंकवादी सूची प्रस्तावों पर एक संवाद शुरू किया।

भारत-अमरीका सामरिक सहयोग :

9/11 के आतंकी घटना के साथ अमरीका भारत सामरिक सहयोग के वास्तरिक पृश्ठभूमि का निर्माण हुआ। इस घटना के उपरान्त दोनों देशों द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने हेतु बिना शर्त समर्थन देने तथ संयुक्त तन्त्र के विकास एवं शांति व्यवस्था बनाये जाने हेतु विभिन्न कदम

उठाए गये। दोनों देशों के मध्य सन् 2004 में 'संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रृँखला' का शुभारम्भ हुआ। 2005 ई0 में दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग को अधिक मजबूत करने हेतु 'न्य फ्रेम फॉर दि यू0एस0ए0-इण्डिया डिफेंस रिलेशनशिप' पर एक ऐतिहासिक समझौतासम्पन्न हुआ जिसके अन्तर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों 'ज्ञानात्मक विकास', 'सैन्य-हथियार','द्विपक्षीय सुरक्षा' एवं 'बहुपक्षीय सुरक्षा' के मुद्दे पर सहमति बनी। इसके साथ-साथ इस समझौते के माध्यम से दोनों देश संयुक्त रूप से शस्त्र उत्पादन पर भी सहमत हुये। जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य जहाँ तकनीकि साझेदारी का मार्ग खुलता है वहीं दूसरी तरफ भारत का एक शस्त्र आयातक देश होने का मिथ भी टूटेगा। संयुक्त रूप से शस्त्र उत्पादन के साथ-साथ भारत द्वारा सन् 2008 में 1 बिलियन डॉलर, सन् 2009 में 2.1 बिलियन डॉलर तथा सन् 2014 में 4.1 बिलियन डॉलर के सैन्य सामाग्री का आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में अमरीकी शस्त्र उत्पादक कम्पनियों की आसान पहुंच भी सम्भव हुयी है जिसके फलस्वरूप इस बात की पूरी सम्भावना है कि दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग आगामी वर्शो में और अधिक समृद्ध हो। किन्तु दोनों देशों के मध्य बढ़ते सामरिक सहयोग की आड़ में अमरीकी रणनीति को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता क्यांकि अमरीका भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता के माध्यम से एशिया में विशेशतः हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में भारत की समृद्ध होती भूमिका के माध्यम से इस क्षेत्र में शक्ति सन्तुलन स्थापित करना चाहता है। दोनों देशों के मध्य बढ़ते सामरिक सहयोग का परिणाम यह रहा है कि रूस की चीन एवं पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। इतना ही नहीं इस सम्बन्ध का प्रभाव भारत-चीन सम्बन्ध,अमरीका-चीन तथा अमरीका-पाकिस्तान सम्बन्धों पर भी स्पश्टतः देखा जा सकता है जैसा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमरीका द्वारा पाकिस्तान को स्पश्ट शब्दों में यह संदेश दिया गया कि वहाँ भारत के राजनीतिक हितों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

जून 2016 में मोदी एक बार फिर अमरीका की यात्रा पर गये। प्रधानमन्त्री के रूप में मोदी की यह चौथी अमरीकी यात्रा थी जबकि अमरीकी राश्ट्रपति ओबामा से यह सातवीं मुलाकात थी। मोदी की इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी -

- आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग।
- अमरीका ने डज्ब्त्एवं परमाणु आपूर्ति कर्ता देशों के समूह ;छैळद्धमें भारत की सदस्यता हेतु पूर्ण समर्थन दिये जाने का वायदा किया।

इसके अतिरिक्त चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' (ठठव्त्) की महत्वाकांक्षी पहल, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में बदलते शक्ति सन्तुलन एवं चीन सागर सहित इस क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव तथा उत्तर कोरिया के उग्र व्यवहार को सन्तुलित करने तथा आतंकवाद का समाधान एवं समुद्री सुरक्षा स्थापित करने की दृश्टि से भारत-अमरीका-जापान-आस्ट्रेलिया के मध्य निर्मित चतुश्कोणीय वार्ता-फन्।क्अतिमहत्वपूर्ण है, जिसकी प्रथम वार्ता फिलीपींस में सम्पन्न 31 वें आसियान सम्मेलन के दौरान उससे इतर फिलीपींस में ही सम्पन्न हुयी। इस चतुश्कोणीय वार्ता में भारतीय भूमिका भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख तथा महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिए सामरिक दृश्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

भारत-अमरीका सम्बन्ध के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अन्तर्गत अमरीकी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने वक्तव्य में पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा बहुपक्षीय मंचों पर न उठाए जाने की चेतावनी दी, जबकि यही कश्मीर मुद्दा कभी भारत एवं अमरीका के मध्य व्याप्त कटुता का एक प्रमुख कारक था। ये सभी घटनाक्रम दोनां देशों के मध्य मजबूत होते रिश्ते का परिचायक है।

भारत-अमरीका असैन्य सहयोग :

भारत में सन् 2004 में राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सन् 2004 के संसदीय चुनाव में सोनिया गॉधी के नेतृत्व में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' (यूपीए) सबसे बड़ा दल बन कर उभरा तथा विभिन्न दलों के सहयोग से डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का

गठन हुआ। सन् 2005 में जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमरीका के राश्ट्रपति बने। यही वह दौर था जब दोनों देशों के मध्य असैन्य सहयोग में अधिक भागीदारी पर बल दिया गया, जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के मध्य ऊर्जा सहयोग, आर्थिक सहयोग, उच्च प्रोद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विकसित होते सम्बन्ध को सम्मिलित किया जाता है।

जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल में अमरीका का प्रमुख प्रयास 'भारत-अमरीका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग' को लेकर था, जिसमें भारत को 'अन्तर्राश्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी' ;प्।म्।द्धके प्रावधानों के अन्तर्गत लाये जाने का उद्देश्य निहित था। अन्ततः सन् 2005 में दोनों देशों के मध्य 'नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग' की रूपरेखा तय की गयी तथा सन् 2007 में दोनों देशों के शीर्श नेतृत्व द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये गये। अमरीकी संसद (कांग्रेस) ने इस समझौते को स्वीकृति देने के लिए अमरीकी विधानां में संशोधन हेतु 'हेनरी हाइट' ;भ्मदमतल भ्पहीजद्धअधिनियम पारित किया क्योंकि पूर्ववत् अमरीकी विधान के अनुसार अमरीका किसी ऐसे देश को परमाणु ईंधन नहीं दे सकता जिसनें छच्ज्पर हस्ताक्षर न किये हों। अन्ततः 2 फरवरी सन् 2009 को भारत एवं 'अन्तर्राश्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी' ;प्।म्।द्धके मध्य 'प्दकपं ैचमबपपिब ैं ंमिहनंतक ।हतममउमदज' सम्पन्न हुआ, जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत भारत अपने 65 प्रतिशत (14) परमाणु संयत्रों को प्।म्। के निरीक्षण के लिए खोल दिया। अमरीका भारत से नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते के उपरान्त 'विखण्डनीय सामाग्री कटौती व्यवस्था' 'मिसाइल प्रोद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था' एवं 'परमाणु अप्रसार' पर भारत से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है।

मार्च सन् 2014 में दोनों देशों के मध्य 'ऊर्जा सम्वाद' का आयोजन हुआ, जिसमें तेल, गैस, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने के साथ-साथ उस पर सहमति भी बनी। सितम्बर 2014 में प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नें अपनी ने अमरीका यात्रा के दौरान 'भारत-अमरीका असैन्य परमाणु समझौते' के कार्यान्वयन का विश्वास दिलाया तथा उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भारत-अमरीका असैन्य सम्बन्ध के अन्तर्गत यदि तकनीकी, सूचना-प्रोद्योगिकी एवं विकास की बात करें तो भारत के इस ओर बढ़ते कदम अमरीका को निरन्तर अपनी तरफ आकर्शित किया है। भारत में कार्यान्वित 'डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम' के साथ-साथ 'ई-गवर्नेंस' के सन्दर्भ में दोनों देशों द्वारा विशेश प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। इसके साथ-साथ भारत द्वारा प्रस्तावित 'ज्ञान' (वैश्विक अकादमी नेटवर्क पहल-जीआईएएन) का अमरीकी राश्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्वागत किया गया, जिसके अन्तर्गत 1000 शिक्षाविदों को भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु भारत द्वारा आमन्त्रित किया जायेगा। तकनीकी क्षेत्र में भी दोनों देशों द्वारा उल्लेखनीय पहल की गयी है, जिसके अन्तर्गत भारतीय अन्तरिक्ष शोध संस्थान 'इसरो' एवं अमरीका के नेशनल एरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 'नासा' के संयुक्त मिशन 'नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार' (एन0आई0एस0ए0आर0) से समबद्ध समझौता होने की सम्भावना भी व्यक्त की गयी।

यदि हम इक्कीसवीं सदी में भारत-अमरीका आर्थिक सम्बन्धों की बात करें तो जहाँ दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार सन् 2001 में 13.48 अरब डॉलर था वहीं यह स्तर 2014 में लगभग 100 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। दोनों देशों द्वारा आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु 'ट्रेड पॉलिसी फोरम' 'भारत-अमेरिका वित्तीय आर्थिक साझेदारी' 'भारत-अमरीका वाणिज्यिक वार्ता' तथा 'भारत-अमरीका सीईओ फोरम' का आयोजन किया गया। भारत-अमरीका के आर्थिक सम्बन्ध में यह उत्साहजनक सुधार दोनों देशों के मध्य असैन्य साझेदारी के बढ़ते स्तर को व्यक्त करता है किन्तु जब हम भारत में पूंजी निवेश की बात करते हैं तो अमरीका की भूमिका कुछ कमतर दिखायी देती है। ऑकड़ों के हिसाब से सन् 2000 से 2009 के मध्य भारत में हुये कुल विदेशी पूंजी निवेश में अमरीकी भागीदारी 7.56 प्रतिशत रही है, जो भारत में विदेशी निवेश की दृश्टि से सर्वोच्च दस देशों की सूची में तृतीय है। वर्ष 2023 में वस्तुओं एवं सेवाओं में समग्र द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी अमेरिका था। 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 40 बिलियन से अधिक का निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप

425,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए। इक्विटी निवेश, सह-बीमा, अनुदान, व्यवहार्यता अध्ययन और तकनीकी सहायता को सक्षम करने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सहयोग (क्थ्ब्) के बीच वर्ष 2022 में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 2024 तक क्थ्ब्का भारत पोर्टफोलियो 100 से अधिक परियोजनाओं में लगभग 4.0 बिलियन था।

अनुसंधान नवाचार व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल

- दोनों देश के नेताओं ने 'प्छक्न्ै इनोवेशन' के शुभारंभ की घोषणा की है जो यू.एस.-भारत उद्योग एवं शैक्षणिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ ही अंतरिक्ष, ऊर्जा व अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा।
- अमेरिकी एवं भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के महत्व को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर शोध के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और भारत के 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' के बीच एक नई साझेदारी की घोषणा की गई है।
- दोनों नेताओं ने 16 वर्ष पूर्व अंतिम रूप दिए गए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के ढाँचे के तहत भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में मदद करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया।
- इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त उत्पादन की पहल भी की।
- दोनों देशों ने यू.एस.-भारत ट्रस्ट (ज्तंदेवितउपदह जीम त्मसंजपवदेपच न्जपसप्रपदह ेजतंजमहपब ज्मबीदवसवहल . ज्त्ने्ज) पहल की शुरुआत की घोषणा की। यह रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को उत्प्रेरित करेगी। इस पहल के हिस्से के रूप में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भी विश्वसनीय एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई है।

मोदी कार्यकाल में भारत-अमरीका सम्बन्ध :

सन् 2010 में भारत द्वारा परमाणु क्षति के लिए 'नागरिक दायित्व अधिनियम' लागू किया जाना, अमरीकी राश्ट्रपति ओबामा की यूरोप एवं एशिया में व्याप्त समस्याओं में व्यस्तता तथा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह की भारत की घरेलू परिस्थितियों से जूझते रहने के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ होते सम्बन्ध में एक ठहराव आ गया था। इसी बीच मई 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा 'राश्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन' (एन0डी0ए0) एक बार पुनः सत्ता में आयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ।

भारत अमरीका सम्बन्धों में आये ठहराव को दूर करने के उद्देश्य के साथ सितम्बर सन् 2014 में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमरीका पहुँचे। मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 'परमाणु सहयोग' 'असैन्य व सैन्य, आसूचना तथा परामर्श' के सम्बन्ध में प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। सन् 2014 में ही दोनो देशों के मध्य 'ज्ञान' (ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्क-ळप्।छद्धकी पहल की गयी, इस पहल का अमरीकी राश्ट्रपति ओबामा द्वारा स्वागत किया गया। इस पहल के अन्तर्गत अमरीका से प्रतिवर्श 1000 शिक्षाविदों को भारत के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। प्रधानमन्त्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अमरीकी राश्ट्रपति को भारत आने हेतु आमन्त्रित भी किये।

प्रधानमन्त्री मोदी के आमन्त्रण पर अमरीकी राश्ट्रपति बराक ओबामा 24 जनवरी, 2015 को भारत यात्रा पर आए। राश्ट्रपति ओबामा अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय गणतन्त्र दिवस समारोह 2015 में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुये। अमरीकी राश्ट्रपति की यह यात्रा एक

ऐतिहासिक यात्रा रही क्योंकि बराक ओबामा राट्रपति के रूप में भारत की दो बार यात्रा करने वाले तथा भारतीय गणतन्त्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने वाले पहले अमरीकी राश्ट्रपति बने। अमरीकी राश्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान 'विशाखापत्तनम्, इलाहाबाद एवं अजमेर' को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये। अमरीका द्वारा भारत में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एक अरब डॉलर की एक्जिम बैंक सुविधा देनी की घोशणा भी की गयी।

इसके उपरान्त जून 2016 में प्रधानमन्त्री मोदी एक बार फिर अमरीका की यात्रा पर गये। प्रधानमन्त्री के रूप में मोदी की यह चौथी अमरीकी यात्रा थी जबकि अमरीकी राश्ट्रपति ओबामा से यह सातवीं मुलाकात थी। मोदी की इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी -

- स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग।
- भारत परमाणु ऊर्जा निगम एवं अमरीकी कम्पनी वेस्टिंग हाउस के मध्य भारत में 6 परमाणु संयत्र लगाने हेतु समझौता हुआ।

जनवरी सन् 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प अमरीका के राश्ट्रपति बने। जैसा कि स्पश्ट है कि ट्रम्प कोई पारम्परिक राजनीतिज्ञ नहीं हैं ऐसे में उनकी नीतियों में 'अमरीका सर्वप्रथम' की प्राथमिकता ने यद्यपि कि अमरीका के अन्तर्राट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित किया है किन्तु अमरीका द्वारा अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को स्वीकार करने तथा आस्ट्रेलिया-जापान-भारत के साथ अमरीका के चतुश्कोंणीय नीति पर बल दिया जाना भारत-अमरीका सम्बन्धों को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 'ट्रंप-2.0' के दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्तों का रोडमैप तैयार करता दिखा. इस यात्रा में उन तमाम मुद्दों पर सार्थक बातें हुईं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्तों को गति मिलेगी। चाहे सबसे अहम आर्थिक मसला हो या रक्षा व तकनीक से जुड़े मुद्दे या फिर ऊर्जा सुरक्षा. दोनों नेताओं ने लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने व बहुपक्षीय सहयोग पर भी जोर दिया। साझा बयान में आतंकवाद की निंदा करते हुए बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा गया कि मुंबई व पठानकोट हमलों के गुनहगारों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने के साथ-साथ इस्लामाबाद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं हो। स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी का यह सफल दौरा रहा है। इसका संकेत मोदी-ट्रंप प्रेस वार्ता से भी मिला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में ट्रंप की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर भारत आने का न्योता दिया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुले दिल से स्वीकार किया।

वर्तमान परिदृश्य

भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में जो चरणबद्ध सुधार आरंभ हुए थे और जिन्हें उनके बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा और गहरा किया गया, वह सिलसिला अब बाधित हो गया हैद्य ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ शुल्क और बार-बार किए गए अपमानों ने भारत को चीन के करीब ला दिया है। पिछले सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री ने सात वर्षों के अंतराल के बाद शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया, जहां उनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। ट्रंप यूरोपीय संघ पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वह भारत पर प्रतिबंध लगाए। ट्रंप द्वारा एच-1 बी वीजा और छात्र वीजा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है अभी हाल में एच-1 बी शुल्क को बढ़ा कर एक लाख डॉलर यानि 88 लाख रुपया कर दिया गया। ट्रंप ने उस क्वाड बैठक को रद्द कर दिया है जो इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाली थी। ध्यान रहे कि ट्रंप ने ही अपने पहले कार्यकाल में क्वाड का गठन किया था ताकि चीन पर लगाम कसी जा सके। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में चीन ही विजेता के रूप में उभरा हैद्य

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट का मानना है कि भारत के साथ अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता संभव है। हालांकि ट्रंप शायद इसकी इजाजत न दें। उनके मुताबिक तो भारत ने कुछ उत्पादों पर शुल्क दर शून्य करने की भी पेशकश की है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।

रिश्ते बिगड़ने के पीछे व्यक्तिगत संबंधों में टूटन को भी वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ युद्धविराम में उनकी भूमिका स्वीकार न करने के कारण भारत से नाराज हैं। वह मानते हैं कि उनका यह कदम उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तक दिला सकता है।

ट्रंप के कदमों ने ब्रिक्स में नई जान फूंक दी है। इन कदमो में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर भारी टैरिफ लगाना शामिल है। अब भारत और चीन इस समूह को मजबूत बनाने में लगे हैं। वर्ष 2026 और 2027 में ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता इन्हीं दोनों देशों के पास रहनी है। देखना होगा कि यह सौहार्द कितने समय तक बना रहेगा। खासकर सीमा विवाद और एशिया का सुपर पावर बनने की चीन की इच्छा को देखते हुए। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक जॉन मरशाइमर का कहना है कि पिछली अमेरिका सरकारों की नीतियों ने रूस और चीन को एक-दूसरे के करीब ला दिया, और अब ट्रंप की नीतियां भारत को उनके करीब धकेल रही हैं।

ब्रिक्स भारत को कुछ भू-राजनीतिक लाभ दिला सकता है लेकिन फिलहाल इसके आर्थिक लाभ सीमित हैं। ब्रिक्स प्लस समूह का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) करीब 32 लाख करोड़ डॉलर है जो वैश्विक जीडीपी का 27 फीसदी है। इसका बाजार जी-7 जैसा नहीं है जिसकी कुल जीडीपी 50 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है और वह वैश्विक जीडीपी के 45 फीसदी योगदान करता है। इतना ही नहीं ब्रिक्स प्लस के कुल जीडीपी में 20 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का योगदान अकेले चीन का है। भारत चीन को बहुत कम निर्यात करता है और वहां उसके निर्यात में इजाफा होने की संभावना नहीं है। भारत की समृद्धि की राह निर्यात बढ़ाने और जी-7 देशों से तकनीक जुटाने में है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता इस लक्ष्य के लिए जरूरी है। बिना इसके भारत न केवल अपना सबसे बड़ा निर्यात बाजार खो देगा बल्कि वह चीन प्लस 1 दुनिया में आने वाले नए निवेश से भी वंचित रह जाएगा। वह निवेश अब मेक्सिको, वियतनाम और अन्य उन देशों में जाएगा जहां अमेरिकी टैरिफ कम है।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'हर संकट के बीच एक महान अवसर छिपा होता है।' भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को खुला रखना चाहिए किंतु अपने महत्त्वपूर्ण हितों से समझौता किए बिना। अमेरिका में समृद्ध और प्रभावशाली मानी जाने वाली भारतीय-अमेरिकी लॉबी को भी सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि अमेरिका की भारत नीति में अधिक समझदारी लाई जा सके। ट्रंप की भू-आर्थिक हलचल वह झटका साबित हो सकती है, जिसने भारत को उसके लंबे समय से प्रतीक्षित और अत्यंत आवश्यक दूसरे चरण के सुधारों की ओर धकेला। जो उसे आगे बढ़ाने में सहायक बने। यदि भारत घरेलू स्तर पर मजबूत होता है, तो भू-आर्थिक समीकरण भी भारत के पक्ष में झुकेंगे।

भारत-अमरीका सम्बन्ध एवं भारतीय हित :

सारभूत रूप से इक्कीसवीं सदी के विभिन्न घटनाक्रम भारत-अमरीका सम्बन्ध में निकटता के स्पश्ट प्रमाण हैं मगर अमरीका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियॉ भारत के राश्ट्रीय हित को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत-अमरीका सम्बन्ध समीक्षा योग्य है। इतना ही नहीं दोनों देशों के मध्य बढ़ती नजदीकियाँ अन्तर्राश्ट्रीय राजनीति के विश्लेशकों को स्वमेव अपनी तरफ आकर्शित करती हैं। भारत-अमरीका सम्बन्ध के सन्दर्भ में भारतीय हित को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता हैः प्रथम दोनों देशों के मध्य निकटता भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व 'गुट-निरपेक्षता' के ठीक विपरीत है जो भारत के बहुपक्षीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में समीचीन नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे भारत के एक 'गुट-निरपेक्ष' देश के रूप में अर्जित साख भी प्रभावित होगी। किन्तु येरूसलम को इजराइल की राजधानी घोशित करने के मुद्दे पर संयुक्त राश्ट्र महासभा में भारत द्वारा अमरीका एवं इजराइल दोनों के विरूद्ध मतदान करके भारत नें यह स्पश्ट कर दिया है कि वह अपने विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व 'गुट निरपेक्षता की नीति' के साथ समझौता नहीं कर सकता। ध्यातव्य है कि अमरीका के साथ-साथ पिछले कुछ वर्शां में इजराइल के साथ भी भारत के सम्बन्ध मजबूत हुये हैं।

द्वितीय, रूस की उपेक्षा करके भारत द्वारा अमरीका के साथ अत्यधिक निकटता भारत के राष्ट्रीय हित के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भारत का परम्परागत मित्र देश रूस उन परिस्थितियों में भारत के साथ खड़ा था जब भारत को उसकी सर्वाधिक अवश्यकता थी। भारत-पाक युद्ध के समय सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद में भारत के पक्ष में तीन बार वीटो का प्रयोग किया गया, सन् 1998 में पोखरण परीक्षण के उपरान्त परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के कई सदस्य देशों द्वारा घोर विरोध के बावजूद रूस भारत को परमाणु ईधन आपूर्ति करता रहा, रूस ने भारतीय असैन्य परमाणु कार्यक्रम की सहायता तब की जब भारत के लिए चारो तरफ से दरवाजे बन्द हो चुके थे। प्रश्न यह है कि क्या हम अमरीका से रूस जैसा सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं? अमरीकी रणनीति एवं उसके राश्ट्रीय हित को देखते हुये इस प्रश्न का उत्तर कदाचित् 'न' में ही मिलेगा।

तृतीय, भारत एक तरफ अमरीका के अधिक निकट जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 'ब्रिक्स' एवं 'शंघाई सहयोग संगठन' के माध्यम से रूस एवं चीन के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। प्रश्न यह है कि क्या भारत अपने राश्ट्रीय हित के सन्दर्भ में रूस एवं चीन के साथ-साथ अमरीका को भी सन्तुलित कर पायेगा? क्योंकि पिछले कुछ वर्शों के घटनाक्रम स्पश्ट करते हैं कि जैसे-जैसे भारत अमरीका के निकट गया है रूस एवं चीन की पाकिस्तान के साथ नजदीकियाँ बढ़ती गयी हैं। अन्तर्राट्रीय परिदृश्य में दक्षिण एशिया एवं हिन्द महासागर का बढ़ता महत्व भारत को इस विशय पर सोचने को मजबूर करता है। हमारी दृश्टि से भारत को इन सभी पहलुओं पर पुनरावलोकन करना समीचीन होगा।

निश्कर्श :

शीत युद्ध की समाप्ति के पूर्व भारत व अमरीका के मध्य व्याप्त कटुता एवं शीत युद्ध की समाप्ति तथा सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के मध्य बढ़ती निकटता भारतीय विदेश नीति एवं भारत के राश्ट्रीय हित की दृश्टि से महत्वपूर्ण है। 11 सितम्बर 2001 को अमरीका स्थित विश्व व्यार केन्द्र एवं 13 दिसम्बर 2001 को आतंकी संगठन लस्कर-ए-तोयबा एवं जैस-ए-मोहम्मद द्वारा भारतीय संसद पर हुये आतंकी हमले के बाद दोनों दोशों के मध्य आतंकवाद को लेकर सहयोगात्मक रवैया रहा है। इतना ही नहीं दोनों देशों के शीर्श नेतृत्व द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध बार-बार अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गयी हैं।

सैन्य सम्बन्ध की बात करें तो भारत की सैन्य उपकरण आयातक देश का मिथक टूटा हैं अब सन् 2005 के समझौते के अन्तर्गत दोनां देश संयुक्त रूप से सैन्य उपकरणों का निर्माण कार्य कर रहे हैं। निःसन्देह एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के राश्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में आगामी कुछ वर्शो में अमरीका के साथ भारत का सम्बन्ध अतिमहत्वपूर्ण होगा।

गौरतलब है कि किन्हीं दो देशों के मध्य अधिक निकटता उनके (अन्य देशों के साथ)द्विपक्षीय सम्बन्धों को भी प्रभावित करती है यह स्थिति पाकिस्तान, चीन एवं रूस के सन्दर्भ में स्पश्टतः देखी जा सकती है। जैसे-जैसे भारत एवं अमरीका के सम्बन्ध मधुर होते गये हैं, पाकिस्तान एवं चीन के साथ रूस की निकटता बढ़ती गयी है।अमेरिका में समृद्ध और प्रभावशाली मानी जाने वाली भारतीय-अमेरिकी लॉबी को भी सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि अमेरिका की भारत नीति में अधिक समझदारी लाई जा सके। ट्रंप की भू-आर्थिक हलचल वह झटका साबित हो सकती है, जिसने भारत को उसके लंबे समय से प्रतीक्षित और अत्यंत आवश्यक दूसरे चरण के सुधारों की ओर धकेला। जो उसे आगे बढ़ाने में सहायक बने। यदि भारत घरेलू स्तर पर मजबूत होता है, तो भू-आर्थिक समीकरण भी भारत के पक्ष में झुकेंगे।ऐसी स्थिति में आवश्यक्ता इस बात की है कि अमरीका के साथ मजबूत होते रिस्ते को चीन एवं रुस से जुड़े अपनें इतना राश्ट्रीय हितों के सापेक्ष सन्तुलित बनाये रखें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- यादव, आर0एस0 -'भारत की विदेश नीति', पियर्सन, दिल्ली, 2013
- प्रो0 मो0 बदरूल, आलम -'भारत-अमरीका सम्बन्ध की ऐतिहासिक समीक्षा और मोदीमय अमरीका', वर्ल्ड फोकस - भारत की नई विदेश नीति, भाग-1, अंक-35, फरवरी 2015
- सम्पादकीय, दैनिक जागरण समाचार पत्र, 8 जून 2016
- डॉ0 मोनिस, तौरंगबम और मिस आकृति, सेठी -'भारत-अमरीका सम्बन्ध : लकवाग्रस्त नीति से नई गतिशीलता तक', वर्ल्ड फोकस, भारत की नई विदेश नीति, भाग-2, अंक-36, मार्च 2015
- द हिन्दू – लखनऊ
- Agarwala, Rina. "Divine Development: Transnational Indian Religious Organizations in the United States and India." International Migration Review 50, no. 4 (2016): 910–50.
- Bajpai, Kanti. "India and the United States." South Asian Survey 15, no. 1 (2008): 33–47.
- Fink, Leon. "Siren Song of Economic Development: U.S. Missions to India, 1952–1975" in Fink, Undoing the Liberal World Order: Progressive Ideals and Political Realities Since World War II (Columbia UP, 2022)
- Ganguly, Sumit, and Andrew Scobell. "India and the United States." World Policy Journal 22, no. 2 (2005): 37–43.
- Gopal, Sarvepalli. Jawaharlal Nehru: a Biography Volume 1 1889-1947 (1975); Jawaharlal Nehru Vol. 2 1947-1956 (1979); Jawaharlal Nehru: A Biography Volume 3 1956-1964 (2014), detailed coverage of diplomacy
- Gould, H.A. and S. Ganguly, eds. The hope and the reality: US-Indian relations from Roosevelt to Reagan (1992).
- Govil, Nitin. Orienting Hollywood: A Century of Film Culture Between Los Angeles and Bombay (NYU Press, 2015)
- Travis, Thom A. "United States-India Relations: Obstacles and Opportunities." India Quarterly: A Journal of International Affairs 42, no. 4 (1986): 381–90.

- Wangwhite, Sherry W. "China's reactions to the India deal implications for the United States." Thesis, Monterey, Calif.: Naval Postgraduate School, 2007.

- Yousafzai, Iftikhar Ahmad, and A. Z. Hilali. "India's Role as a Determinant in Pakistan-US Relations (2005-2015)." Review of Applied Management and Social Sciences 4, no. 1 (2021): 285–93.

Citation in APA 7th Edition: *यादव, . हिमांशु . (2025). भारत अमेरिका के सम्बन्ध के विविध आयाम. Lyceum india journal of social sciences, 2(5), 78–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.17466271*

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*